(a) whether the terrorism in Kashmir is having a major bearing on the economy and tourist arrival in the State;

(b) if so, the estimate of loss due to terrorist activities in the state; and

(c) steps being taken by Government to curb terrorism in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) It is a fact that terrorist violence in Jammu and Kashmir has had an adverse impact on development and economic activities. The tourism sector especially in the Valley and associated business and trade has been particularly hit, depriving a very large number of people like Hotel-owners, Shikara-Wallas, ponywallas, etc. of their livelihood, and a sizeable loss in the form of related revenues to the State exchequer.

(c) Sustained pressure is being maintained on the militants with a view to containing violence and disruption of normal activities. The steps taken in this direction include stepped up vigilance and patrolling on the Border/LOC to prevent infiltration of terrorists and weapons, etc., streamlining of the intelligence machinery to enable targetted operations, ensuring close coordination between various operational agencies, activisation, and increasing the involvement of the State Police in anti-terrorist operations; strengthening of security arrangements in vulnerable and far-flung areas; and securing people's cooperation in antiterrorist operations. Simultaneously measures have been taken to step up the pace of development and economic activities and reactivate the normal activities of the civil administration which have also helped to isolate the militants and bring the people into the mainstream of normal life and activity.

Payment of wages to PSUs employees on time

1742. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to State:

(a) whether the assurance given by Government that employees of Jessop and Company will be paid their wages and other dues regularly each month has been acted upon;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the measures Government proposes in order to ensure that employees of all public sector undertakings receive their contractual dues each month on a regular basis without any exception?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) Jessop & Company has been persistantly incurring losses. As a result, the company has not been able to pay salary wand wages to their employees for the month of June and July 1995 respectively. In order to pay wages and salary, this Department released Rs. 1.35 crores to Jessop during the current financial year. Since this amount fell short of the requirement of Jessop for clearing its liabilities towards payment of salary and wages upto-date. Other ways & means for paying the wages & salaries are being considered.

ग्रामीण और आदिवासी स्वच्छता कार्यक्रम

1743. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण और आदिवासी स्वच्छता कार्यक्रम हेतु जिलावार क्या कार्य नीति निर्धारित की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में प्रत्येक जिले को वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि आवटित की गई;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रयोजनार्थ जिलावार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है/मिलने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की सामान्य मार्ग दर्शिकाओं के अनुसार कार्य नीति का पालन किया जा रहा है। कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन को 1992-93 में ग्रामीण विकास विभाग से राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग को अंतरित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) 1992-93 से 1995-96 के दौरान जिलावार लक्ष्यों और आवंटित राशि के ब्यौरे विवरण में है नीचे देखिए 1996-97 के लिए लक्ष्य और आवंटन पर परिव्यय के आधार पर अप्रैल, 1996 में निर्णय लिया जाएगा जो कि उस वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(घ) लाभांवित/लाभांवित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 6.7125 लाख है।

विवरण

I. आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु जिलेवार लक्ष्यों के साथ-साथ आवंटित राशि को दर्शाने वाला विवरण

(आवंटन लाख में)

		1992-93		1993-94		1994-95	
क्रमांक	जिले का नाम	लक्ष्य	आवंटन	लक्ष्य	आवंटन	लक्ष्य	आवंटन
1.	भोपाल			310	7.00	820	15.00
2.	रायसेन	1710	5.00	380	43.00	780	18.00
3.	सिहोर	350	2.40	380	24.00	760	10.00
4.	राजगढ़			320	28.60	640	38.67
5.	विदिशा			340	8.00	3.80	21.00
6.	बेतुल			340	8.24	800	21.00
7.	होशंगाबाद			340	13.00	840	21.00
8.	इन्दौर	520	5.00	340	42.00	380	31.00
9.	खांडवा			340	8.24	600	21.00
10.	धार			340	8.00	840	40.00
11.	झबुआ			300	9.00	800	16.00
12.	खारगांव			320	8.20	640	15.00
13.	उज्जैन			320	10.00	840	15.00
14.	रतलाम			320	7.50	840	10.00
15.	मंदसौर			320	10.00	840	16.00
16.	देवास			320	7.00	840	15.00
17.	शाजापुर			320	10.00	840	16.00
18.	ग्वालियर	1175	8.00	380	17.00	760	23.00
19.	दतिया			310	7.00	320	3.00
20.	गुणा			320	8.60	840	20.00
21.	शिवपुरी	1280	8.00	380	27.00	780	27.00

क्रमांक	जिले का नाम	लक्ष्य	आवंटन	लक्ष्य	आवंटन	लक्ष्य	आवंटन
22.	मुरैना			340	5.78	840	8.00
23.	भींड			340	5.74	840	
24.	सागर			340	8.24	840	16.00
25.	दमोह			820	8.00	840	15.00
26.	छत्तरपुर			340	8.00	840	20.00
27.	पन्ना			320	8.00	840	20.00
28.	टीकमगढ़			320	8.80	840	20.00
29.	रिवा			340	9.80	840	20.00
30.	सतना			340	6.78	840	15.00
31.	शाहडोल			340	8.00	840	16.00
32.	सिधी			320	5.73	840	16.00
33.	जबलपुर			340	8.80	840	25.00
34.	नरीसहपुर			320	9.00	840	28.00
35.	बालाघाट			340	10.00	840	20.00
36.	मांडला			320	8.00	840	24.00
37.	सिओनी			340	10.78	840	21.00
38.	छिंदवाड़ा			340	8.80	840	21.00
39.	रायपुर			340	8.24	840	25.00
40.	दुर्ग			340	8.00	840	10.00
41.	राजनंदगांव			340	8.12	840	15.00
42.	बिलासपुर						
	(क) कोरबा			180	4.50	320	8.00
	(ख) बिलासपुर			160	4.50	320	13.00
43	सरगुजा			180	3.00	840	34.00
	(क) अम्बिकापुर			180	2.40	840	16.00
	(ख) सैकुण्डपुर			320	8.00	840	16.00
44.	रायगढ			160	3.00	820	20.00
45	बस्तर			160	2.50	320	23.00

II. आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(लाख रुपये में)

क्रमांक	जिले का नाम	लक्ष्य	1995-96 आवंटन
1.	भोपाल	800	20.00
2.	रायसेन	1075	26.88
3.	सिहोर	1087	27.18
4.	राजगढ़	1369	34.23
5.	विदिशा	938	23.45

1	2	3	4
6.	बेतुल	827	20.88
7.	होशंगाबाद	1025	25.63
8.	इन्दौर	780	18.60
9.	खांडवा	751	18.78
10.	धार	2098	62.40
11.	झबुआ	358	8.80
12.	खारगांव	1168	23.05
13.	उज्जैन	718	17.05
14.	रतलाम	841	21.03
15.	मंदसौर	700	17.60
16.	देवास	830	20.75
17.	शाजापुर	713	17.83
18.	ग्वालियर	686	17.15
19.	दतिया	300	7.50
20.	गुणा	778	18.46
21.	शिवपुरी	1213	30.33
22.	मुरैना	338	8.46
23.	भींड	287	7.18
24.	सागर	708	17.85
25.	दमोह	858	21.40
26.	छत्तरपुर	1034	25.86
27.	पन्ना	851	21.28
28.	टीकमगढ़	713	17.83
29.	रिवा	734	18.35
30.	सतना	718	17.95
31.	शाहडोल	700	17.50
32.	सिधी	883	24.08
33.	जबलपुर	1425	35.63
34.	नरसिहपुर	1813	40.33
35.	बालाघाट	838	20.85
36.	मांडला	868	24.23
37.	सिओनी	1000	25.00
38.	छिंदवाड़ा	350	21.45
39.	रायपुर	770	18.26
40.	दुर्ग	847	21.18
41.	राजनंदगांव	434	10.85
42.	बिलासपुर		
	(क) कोरबा	406	10.15
	(ख) बिलासपुर	789	16.23
43	सरगुजा	लक्ष्य	आवंटन
	(क) अम्बिकापुर	1247	31.18

1	2	3	4
	(ख) बैकुण्ठपुर	385	8.88
44.	रायगढ़	710	17.75
45	बस्तर		
	(क) जगदलपुर	258	8.40
	कंकर	552	13.05

भूमि के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

1744. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण भूमि के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु 99 जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के नाम क्या हैं और किन-किन जिलों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) क्या सरकार भूमि संबंधी विवादों के शीघ्र निपटान हेतु सम्पूर्ण भूमि का कम्प्यूटरीकरण करने पर विचार करेगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पूंजाभाई पटेल): (क) सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से पूर्व संस्वीकृत 24 प्रायोगिक परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने के अलावा अब तक 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 78 नए परियोजना जिलों को वित्त-पोषित किया है।

(ख) उन जिलों के नाम, जहां कम्प्यूटरीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है, के साथ-साथ जिलों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ग) सरकार देश भर में भूमि रिकार्डों का चरणबद्ध ढंग से कम्प्यूटरीकरण करने पर विचार कर रही है और यह संभावना है कि इससे भूमि विवादों का शीघ्र निपटान करने में मदद मिलेगी।

विवरण

भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत जिलों का राज्यवार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना जिले
1.	आंध्र प्रदेश	1. रंगा रेड्डी
		2. करीमनगर
		3. कुड्डप्पा
		4. नेल्लोर
		5. कुरनूल
		6. पश्चिम गोदावरी
		7. अनंतपुर
		8. श्रीकाकुलम
2.	असम	1. सोनितपुर
		2. कामरूप
		3. नौगांव
		4. करीमनगर
		5. दारंग
3.	बिहार	1. पूर्वी सिंहभूम
		2. संथाल परगनाज
		3. दुमका
		4. गया
		5. मुजफ्फरनगर
		6. भौहारडंग्या
		7. जहानाबाद
4.	गुजरात	गांधीनगर
5.	गोवा	सम्पूर्ण राज्य